उत्तराखंड में आवास और शहरी विकास को रफ्तार देगा हडको

प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना पर चर्चा हुई

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: राज्य में आवास और शहरी विकास योजनाओं को गति देने का काम तेज कर दिया गया है। सचिव आवास डा. आर.राजेश कुमार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर आगे की योजनाओं पर चर्चा की।

सचिव आवास डा. आर. राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना और भविष्य की शहरी विकास रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। कहा, ऐसी योजआएं बनाई जाएं जिससे राज्य की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। खासतौर पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ मकान उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक में सहमति बनी कि उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2047 और वर्ष 2050 तक जरूरतों के अनुसार एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनियोजित आवास विकास पर जोर दिया जाएगा। हडको के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने भरोसा दिलाया कि नए नगरों व टाउनशिप के विकास में हडको राज्य सरकार को हर स्तर पर सहयोग देगा। भूमि विकास, मास्टर प्लानिंग व वित्तीय सहायता में हडको का अनुभव उत्तराखंड के लिए उपयोगी होगा। तय हुआ कि आवास योजनाएं केवल शहरी इलाकों तक सीमित न रहें। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी योजनाबद्ध निर्माण से पलायन पर रोक लगेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्वतीय जिलों में स्थानीय निर्माण तकनीक और पारंपरिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। लागत कम हो, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

सचिव आवास डा. आर.राजेश कुमार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हडको) के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव से परियोजनाओं पर चर्चा की • सूचि

प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ रेंटल हाउसिंग योजना पर भी विशेष फोकस रखा गया। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग को किफायती किराये पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे शहरों में अनियोजित बसावट पर नियंत्रण किया जा सके। बताया गया कि हडको अब तक राज्य में 115 आवासीय और शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी दे चुका है, जिनकी कुल ऋण राशि 1543.34 करोड़ रुपये है।